(e) Vitamin 'A' is sought to be provided to children between 9 months to three years of age; twice a year.

रेलवे द्वारा "व्हीलर एण्ड व्हीलर" नामक फर्म को ही लाइसेंस दिया जाना

*26. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर पुस्तकों, समाचार-पत्रों और अन्य पत्रिकाओं की बिक्री करने के लिये "व्हीलर एण्ड व्हीलर" नामक केवल एक फर्म को ही लाइसेंस दे रखा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्लेटफार्मों पर पुस्तकें, समाचार-पत्र और पत्रिकाएं बेचने के क्या मानदण्ड हैं;

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के लाइसेंस केवल स्वतंत्रता-सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों को ही देने का विचार रखती है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) से (ङ) जी नहीं, बुक-स्टाल लाइसेंसधारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि करार की शर्तों के अनुसार वे साहित्य तथा अन्य पाठ्य-सामग्री प्रदर्शित करें और उसकी ही बिक्री करें, मौजूदा बुक-स्टालों के अलावा, नये आबंटन ज्यादातर सहकारी समितियों, बेरोजगार स्नातकों के एसोसिएशनों और वास्तविक कामगारों/रेलवे बुक स्टालों के वेंडरों की सहकारी समितियों तथा अलग-अलग बेरोजगार स्नातकों आदि के लिए निर्धारित किए जाते हैं, ऐसा समझा जाता है कि इस समय, किन्हीं और कोटियों को इसमें शामिल किया जाना विशेष ग्रुपों के हितों के प्रतिकूल होगा ।

गुजरात में रेलवे फाटकों का निर्माण

*27. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने स्थानों पर रेलवे फाटकों का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) क्या कुछ स्थानों पर यह कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं , और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :

(क) एक ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 31-12-93 ।

Fishing by chartered ball trawlers in EEZ

*23. SHRI MENTA.Y PADMANABHAM: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be plea sed to refer to the news-item appearing in the Economic Times of 9th January 1993 under the Caption "Fishery Joint Venture rejected on. green grounds" and state:

(a) how many chartered bull trawlers are presently authorised to fish *in* our Exclusive Economic Zone:

(b) how many such chartered bull trawlers are actually operating in our Exclusive Economic Zone;

(c) how many fishing companies received renewal or extension of validity for use of chartered bull trawlers in 1992; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN -GOGOI): (a) 13 (Thirteen) pairs of foreign bull trawlers hold valid Charter Permits for fishing in the Indian SEZ as on 19-2-1993.

.(b) As on 19-2-1993, no bull trawlers is operating in our EEZ.

(c) and (d) During the year, 1992, eight companies were granted extension of validity of Charter Permits for bull trawlers. The details are at statement attached.

Statement

Sl. No.	Name of the Company	No. of vessels	Date of expiry of Permit
1.	High Sea Foods Limited . . .	1 Pair	20-5-1993
2.	Ocean Products Shipping Limited	1 Pair	18-6-1993
3.	V. B. C. Exports Limited	2 Pairs	13-2-1993
4.	G.P. Marine Products (I) Limited	2 Pairs	13-2-94 and 21-1-1994
5.	Shrimp India Limited . . .	2 Pairs	20-2-1994
6.	Shrinivasa Enterprises Ltd	2 Pairs	12-3-1994
7.	Star Marines (P) Ltd.	1 Pair	10-6-1994
8.	Golden Ahar Limited	1 Pair	[illegible]-1994
		12 Pairs	

Collusion of a Danish Tanker with a Japanese Vessel

*29. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SHRI VIREN J. SHAH:

WiU the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Government has recently decided to claim compensation from the owners of the Danish oil tanker which "was hit by a Japanese tanker and caught fire leading to oil slick near the Nicobar Islands;

(b) if so, the details of compensation sought; and

(c) what other steps Government propose to take to protect the Indian shore?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Yes, Sir. Claims for the compensation for economic Sand ecological damage are under preparation toy-toe Coast Guard in cwawMaation with Ministry of Surface Transport and Department of